

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या- /2017/XXVII(9)/स्टाम्प-55/2009
देहरादून: दिनांक 12 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

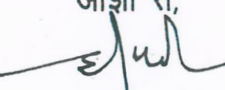
अतः राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, शासन की अधिसूचना संख्या-160/2016/XXVII(9)/स्टाम्प-55/2009, दिनांक 30 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 की तारीख तक ₹ 5,00,000.00 (₹ पांच लाख मात्र) तक के कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या- 91 / (1) / 2017 / XXVII(9) / स्टाम्प-55 / 2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप-निदेशक, लिथो प्रेस, रुड़की को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग-9 को उपलब्ध करा दें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।